Government and some companies located in Great Britain;

(c) whether Government have assured provision of public telephone system on trains; and

(d) if so, the facts and details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) and (b) A Memorandum of Understanding for a pilot project was signed between Ministry of Communications and International Mobile Satellite Organisation (INMARSAT)

(c) and (d) One of the objectives of the pilot project is to study the feasibility of using INMARSAT terminal for voice service in trains.

रेल दावा अधिकरणों में रिक्तियां

*232. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेल दावा अधिकरणों में सदस्यों और अध्यक्षों के कितने पद कब से रिक्त हैं और प्रत्येक अधिकरण में कितने दावे दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं; और

(ख) उक्त अधिकरणों में दुर्घटनाओं के कारण हुई मृत्यु और विकलांगता संबंधी दावों की अधिकरणवार संख्या कितनी-कितनी है?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ): (क)

(क) रेल दावा अधिकरण में सदस्यों के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:—

पीठ	पद	जिस तारीख से पद खाली है वह तारीख	टिप्पणी
पटना	सदस्य (न्यायिक)	21.09.93	नियुक्ति प्रस्ताव जारी कर दिए गए हैं उम्मीदवार
जयपुर	सदस्य (तकनीकी)	09.10.94	की प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा की जा रही है।
चंड़ीगढ़	सदस्य (तकनीकी)	04.01.95	
अहमदाबाद	सदस्य (तकनीकी)	27.01.94	नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये गये हैं।
बम्बई	सदस्य (तकनीकी)	30.09.94	कार्यभार शीघ्र ही सम्हाले जाने की आशा है।
एर्णाकुलम	सदस्य (तकनीकी)	08.11.94	इस पर कार्रवाई की जा रही है।
गुवाहाटी	सदस्य (तकनीकी)	01.02.95	

31.1.95 को वर्तमान स्थिति के अनुसार रेल दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों, में जहां सदस्यों के पद रिक्त है 2 वर्ष से अधिक पुराने लगभग 5890 दावों के मामले लम्बित पड़े हैं। पीठवार स्थिति नीचे दर्शाई गई है:—

पीठ	दो वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े मामलों की संख्या
चंड़ीगढ़	418
जयपुर	4
बम्बई	1433
अहमदाबाद	2355
एर्णाकुलम	95
गुवाहाटी	988
पटना	597
जोड़:	5890

(ख) रेल दावा अधिकरण की उन पीठों में लम्बित पड़े दुर्घटना के दावों के मामलों की संख्या नीचे दी गई है जहां पर सदस्यों के पद रिक्त पड़े हैं:—

पीठ	लंबित पड़े मामलों की संख्या
अहमदाबाद	25
चंड़ीगढ़	8
गुवाहाटी	23
बम्बई	89
पटना	208
एर्णाकुलम	44
जयपुर	15

"मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना"

*233. **श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 1994 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार के पास मध्य प्रदेश सरकार के जिला-वार ऐसे कितने सिंचाई परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित हैं जिनमें वन भूमि डूब क्षेत्र में आती है; और

(ख) उक्त लंबित परियोजनाओं में से जिला-वार कितनी परियोजनाएं आदिवासी परियोजना क्षेत्रों के लिए है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) और (ख) 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना का केवल एक प्रस्ताव अर्थात् शिवपुरी जिले में मोहिनी सागर बांध परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी के लिए लम्बित था। इस प्रस्ताव को दिनांक 3.1.1995 को सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया है। राज्य द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त सिंचाई परियोजना आदिवासी परियोजना क्षेत्रों में नहीं आती है।

Supply of Railway Wagons at Gandhidham and Kandla Stations

*234. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what is the number of railway wagons provided by the railway authorities to Gandhidham and Kandla stations in Kutch District in Rajkot Divison, till 31st March, 1994 for loading and unloading of export and import goods; and

(b) whether Government propose to increase the number of wagons for Gandhidham and Kandla stations to meet the demand of local and State and nation-wide traders and Chambers of Commerce, in the current financial year and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C.K. JAFFER SHARIEF): (a) All import and export traffic offered to and from Gandhidham/Kandla has been loaded. During 1993-94 details of wagons provided for loading and unloading of exports and improts in four wheeler units are given below:—

Loading		*Unloading*	
Broad Gauge	Metre Gauge	Broad Gauge	Metre Gauge
103878	104310	48858	3622

(b) Railways always endeavour to increase the wagon supply. However, wagons are not allocated to a particular sector. The wagons on Indian Railways are in common pool and are supplied in different areas according to priority and demand.